(b) Capital Formation

विकासशील देश के आर्थिक विकास में पूँजी निर्माण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजकोषीय नीति को प्रभावी बनाकर पूँजी निर्माण में वृद्धि की जा सकती है। सरकारी व्यय एवं करों में वृद्धि करके उपभोग में कमी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विदेशी ऋण, विदेशी बचत, बीमा कम्पनी आदि द्वारा भी पूँजी निर्माण में वृद्धि किया जा सकता है।

(c) Justified equal Distribution

वर्तमान समय में राजकोषीय नीति के द्वारा आय की असमानता को दूर करने का प्रयत्न किये जाते हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि करके रोजगार के अवसर को बढ़ाये जाते हैं। प्रगतिशील करारोपण के द्वारा फिजूलखर्ची को रोका जा सकता है तथा निर्धनों के आय स्तर को ऊँचा किया जाता है।

(d) Give Employment

राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी दूर करना होता है इसलिए सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए ताकि निजी एवं सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की जा सके। इसके लिए उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि कर प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना होता है ताकि लोगों की मांग का प्रभाव वस्तुओं की बिक्री पर पड़ सके। इस क्रिया के जारी रहने से रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होती है।

(e) To Remove Inflationary effect

घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा अतिरिक्त क्रय

को घुमाया जाता है। यदि घाटे की पूर्ति करारोपण या ऋण से की जाय तो मुद्रा प्रसार की सम्भावना बहुत कम होती है। परन्तु जब सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए हिनार्थ प्रबन्ध करती है तो मुद्रा प्रसार बढ़ता है। अतः राजकोषिय नीति के द्वारा मुद्रा प्रसार रोका जा सकता है। इसके लिए करारोपण व ऋण के द्वारा लोगों की अतिरिक्त क्रयशक्ति को छिन लिया जाता है। इस क्रिया से लोगों के द्वारा जितनी अतिरिक्त मुद्रा चलन में आती है उतनी ही मुद्रा लोगों की जेब से कर के द्वारा निकाल ली जाती है जिससे मुद्रास्फीति नहीं होता।

परन्तु हीनार्थ प्रबन्ध से पुरानी मुद्रा की मात्रा में नयी मुद्रा की मात्रा मिल जाने से मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है। मुद्रा का चलन-वेग व मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ायी जाती है उस अनुपात में वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ पाता है जिससे मुद्रा प्रसार बढ़ता है।

मुद्रा प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए निम्न उपाय किये जाते हैं -

(1) मुद्रा प्रसार के समय अतिरिक्त क्रयशक्ति ~~लोगों की फिजूलखर्ची को रोका जाना चाहिए।~~ पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए।

(2) प्रगतिशील कर पर करारोपण करके लोगों की फिजूलखर्ची को रोका जाना चाहिए।

(3) अनिवार्य बचतों को प्रोत्साहित एवं ऐच्छिक बचतों के लिए लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए।

④ मुद्रा प्रसार के समय वस्तु कर तथा विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए।

⑤ सरकार को मुद्रा प्रसार रोकने के लिए प्रगामी कर व्यवस्था को अपनाना चाहिए।

इस प्रकार राजकोषिय नीति के द्वारा रोजगार, आर्थिक विकास तथा कीमत में स्थिरता लाई जा सकती है।

Dr Sandhya Rai
Maharaja College